Irregularities in the Modernisation Programmes

1697. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether any demand for setting up a high-level technical committee to investigate into the irregularities in all modernisation programmes has been made; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STEEL & MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के संबंध में सलाहकार समिति

1698. **श्री सुशील बरोंगपा:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए कोई सलाहकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी समिति का गठन न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किए बिना ही इस समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए अक्टूबर, 1993 में एक सलाहकार समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपना कार्य पूरा नहीं किया और अब यह विद्यामान नहीं है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन में संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श की अपेक्षा की गई है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में विभिन्न समुदायों को शामिल करने संबंधी दावों और सिफारिशों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है।

Awarding of "O Unit" of 250 MW to an NRI by NLC)

1699. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "O Unit" of 250 MW was awarded by NLC in favour of NRI:

(b) if so, the details of the proposal with justification for handing over such a cost effective project on the most favourable terms to NRI without proven track record and financial back-up and without compliance with the set procedure;

(c) whether it is a fact that in spite of the liberal terms, the project has hardly made any progress while the NLC is proposing to undertake another power project;

(d) if so, whether Government would institute an enquiry into the deal; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) Government of India approved the transfer of the Zero Unit Project to M/s. ST Power Systems in the year 1992 keeping in mind the policies and procedures as well as the acute resource crunch being faced by Neyveli Lignite Corporation (NLC) at that point of time. All aspects of the proposal were considered at various levels and was approved by the competent authorities.

(c) Fuel supply and Power Purchase/ Guarantee Agreements are under discussion and negotiation. Further progress on this project is dependent on the outcome of these. It is true that NLC has underta-